भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2243

14 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"फेम इंडिया योजना"

2243. श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में (हाइब्रिड और) इलैक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण का विनिर्माण (फेम) योजना की शुरुआत के बाद से (हाइब्रिड) और इलैक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की निकट भविष्य में तिपहिया वाहनों (ऑटो) को ई-रिक्शा से प्रतिस्थापित करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार देश में इलैक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त योजना के प्रारंभ से उत्तर प्रदेश राज्य में इलैक्ट्रिक वाहनों के प्रतिशत में वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम तैयार की थी। स्कीम का चरण-1, 895 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय से 31 मार्च, 2019 तक उपलब्ध था। फेम इंडिया स्कीम के इस चरण में चार मुख्य क्षेत्रों अर्थात् प्रौद्योगिकीय विकास, मांग सृजन, प्रायोगिक परियोजना और चार्जिंग अवसंरचना घटक पर बल दिया गया था।

स्कीम के पहले चरण में, कुल 359 करोड़ रुपये (लगभग) के मांग प्रोत्साहन से लगभग 2.8 लाख हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के लिए सहायता दी गई थी। साथ ही, स्कीम के पहले चरण के तहत यथासंस्वीकृत 425 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसों को लगभग 280 करोड़ रुपये के सरकारी प्रोत्साहन से देश के विभिन्न शहरों में तैनात किया गया है। भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम-इंडिया स्कीम के चरण-। के तहत 43 करोड़ रुपये (लगभग) से लगभग 520 चार्जिंग स्टेशनों/अवसंरचना की भी संस्वीकृति दी थी।

ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, नॉन-फेरस मैटेरियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (एनएफटीडीसी), अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) आदि जैसे विभिन्न संगठनों/संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं,यथा- परीक्षण अवसंरचना की स्थापना, विद्युतीकृत परिवहन में उन्नत अनुसंधान के लिए 'उत्कृष्टता केंद्र' की स्थापना, बैटरी इंजीनियरिंग आदि के लिए लगभग 158 करोड़ रुपये की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं।

फेम इंडिया स्कीम के चरण-I के दौरान प्राप्त परिणाम और अनुभव के आधार पर और उद्योग और उद्योग संघों सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श के बाद सरकार ने कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए फेम इंडिया स्कीम के चरण-II को अधिसूचित किया है। यह चरण मुख्य रूप से सार्वजनिक और साझाकृत परिवहन के विद्युतीकरण के लिए सहायता देने पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य मांग प्रोत्साहन के माध्यम से 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों के लिए सहायता प्रदान करना है।

फेम इंडिया स्कीम, चरण-II के अंतर्गत मांग प्रोत्साहन के माध्यम से 15.02.2023 तक 8,82,967 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सहायता प्रदान की गई है। साथ ही, भारी उद्योग मंत्रालय ने इस स्कीम के तहत 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इंट्रासिटी और इंटरसिटी प्रचालन के लिए 65 शहरों/एसटीयू/सीटीयू/राज्य सरकार की इकाईयों के लिए 6315 ई-बसें स्वीकृत की हैं। मंत्रालय ने फेम इंडिया (भारत में हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम के चरण-II के तहत 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 68 शहरों में 2877 चार्जिंग स्टेशनों को भी संस्वीकृति दी है। साथ ही, फेम इंडिया स्कीम के चरण-II के अंतर्गत 9 एक्सप्रेसवे और 16 राजमार्गों पर 1576 चार्जिंग स्टेशन भी संस्वीकृत किए गए हैं।

(ख) और (ग): भारी उद्योग मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसके अलावा, फेम इंडिया स्कीम, चरण-II के तहत 15.02.2023 तक 81,172 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए सहायता प्रदान की गई है।

(घ): सरकार ने वाहनों के घरेलू विनिर्माण को समर्थन प्रदान करने के लिए 15 सितंबर, 2021 को 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम को स्वीकृति दी। इलेक्ट्रिक वाहन इस उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम के तहत कवर किए जाते हैं।

(ङ): पंजीकरण प्रमाणपत्र के संबंध में वाहन-4 केन्द्रीकृत डाटाबेस में उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिनांक 09.03.2023 की स्थिति तक उत्तर प्रदेश राज्य में उपलब्ध विद्युत वाहनों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**श्रेणीवार इलेक्ट्रिक वाहन संख्या**			**कुल इलेक्ट्रिक वाहन संख्या**
		दुपहिया	**तिपहिया**	**चौपहिया और इससे ऊपर**	
1	उत्तर प्रदेश	45,130	4,18,794	1,508	**4,65,432**

***